Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC | SSC | BANK RAILWAY Exam

BANKING AND FINANCIAL AWARENESS

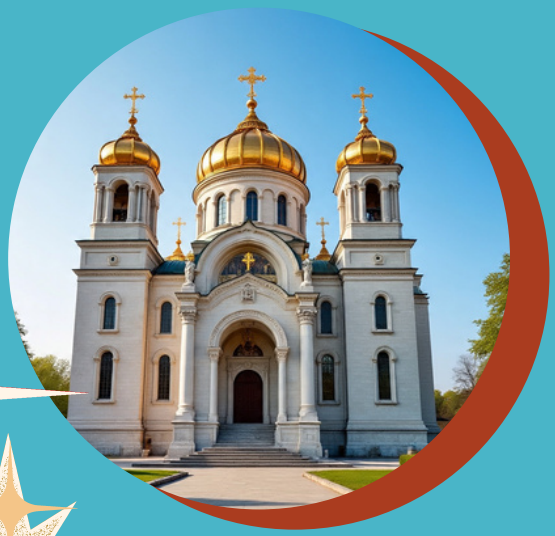

26 OCT - 1 NOV 2025

5TH WEEK OF OCTOBER

50+ MCQ with detailed explanation

- Banking & finance
- Banking Facilities
- Banking Appointment
- Banking Agreement

Ques: Which banks provided the $215 million term loan to AI Fleet Services IFSC for financing six Boeing 777-300 ER aircraft for Air India?
कौन से बैंकों ने एयर इंडिया के लिए छह बोइंग 777-300 ER विमानों के वित्तपोषण हेतु AI Fleet Services IFSC को $215 मिलियन का टर्म लोन दिया?

A) Standard Chartered and Bank of India / स्टैंडर्ड चार्टर्ड और बैंक ऑफ इंडिया
B) State Bank of India and Axis Bank / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक
C) HDFC Bank and ICICI Bank / एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक
D) Citibank and Kotak Mahindra Bank / सिटीबैंक और कोटक महिंद्रा बैंक
E) Punjab National Bank and IDBI Bank / पंजाब नेशनल बैंक और आईडीबीआई बैंक

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

• A $215 million term loan was provided to AI Fleet Services IFSC (AIFS), the leasing subsidiary of Tata Group–owned Air India, based in GIFT City, for financing six Boeing 777-300 ER aircraft to be leased to Air India.
• $215 मिलियन का टर्म लोन AI Fleet Services IFSC (Tata Group–owned Air India की लीजिंग सहायक कंपनी को (GIFT सिटी में स्थित, छह बोइंग 777-300 ER विमानों के वित्तपोषण के लिए दिया गया।
• The loan was jointly given by Standard Chartered and Bank of India (BoI), with Standard Chartered acting as the lead structuring bank.
• यह लोन स्टैंडर्ड चार्टर्ड और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड लीड स्ट्रक्चरिंग बैंक के रूप में कार्य कर रहा था।
• Both banks also served as Mandated Lead Arrangers and Bookrunners for the transaction.
• दोनों बैंकों ने इस लेनदेन के लिए मंडेटेड लीड अरेंजर और बुकरनर के रूप में भी काम किया।
• The financing will enable Air India to expand its fleet and support its operational and leasing plans.
• यह वित्तपोषण एयर इंडिया को अपने विमान बेड़े का विस्तार करने और परिचालन एवं लीजिंग योजनाओं का समर्थन करने में सक्षम बनाएगा।

About Standard Chartered Bank :

- Established : 1969

- HQ : Mumbai
- Group CEO : Bill Winters
- Tagline : Here for good

Ques: ICICI Bank has partnered with which institution to construct a new cancer care centre in Maharashtra?
महाराष्ट्र में नया कैंसर केयर सेंटर बनाने के लिए ICICI बैंक ने किस संस्थान के साथ साझेदारी की है?

A) AIIMS Delhi / एम्स दिल्ली
B) Tata Memorial Centre (TMC) / टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी)
C) Apollo Hospitals / अपोलो हॉस्पिटल्स
D) Fortis Healthcare / फोर्टिस हेल्थकेयर
E) Medanta Hospital / मेदांता हॉस्पिटल

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• ICICI Bank has partnered with the Tata Memorial Centre (TMC) to build a new cancer care building named 'ICICI Foundation Block for Radiation Oncology' at ACTREC, Navi Mumbai, Maharashtra.
• ICICI बैंक ने टाटा मेमोरियल सेंटर)TMC) के साथ मिलकर नवी मुंबई, महाराष्ट्र स्थित ACTREC परिसर में 'ICICI फाउंडेशन ब्लॉक फॉर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी' नामक नए कैंसर केयर भवन के निर्माण की शुरुआत की है।
• The ₹625 crore project is funded through ICICI Bank's CSR contribution and will include advanced radiation therapy centres equipped with cutting-edge technologies.
• यह ₹625 करोड़ की परियोजना ICICI बैंक के CSR योगदान से वित्तपोषित है और इसमें अत्याधुनिक रेडिएशन थेरेपी सुविधाएं शामिल होंगी।
• The initiative is part of ICICI Bank's ₹1,800 crore commitment to TMC for constructing three cancer care buildings — in Navi Mumbai (Maharashtra), Mullanpur (Punjab), and Visakhapatnam (Andhra Pradesh).
• यह पहल ICICI बैंक की ₹1,800 करोड़ की प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसके तहत तीन अत्याधुनिक कैंसर केयर भवन नवी मुंबई, मुल्लनपुर और विशाखापट्टनम में बनाए जा रहे

हैं।
• The new facility is expected to be completed by 2027.
• इस नई सुविधा को 2027 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है।

Ques: As per the Notaries (Amendment) Rules, 2025, what is the new maximum number of Notaries allowed to be appointed in Gujarat?
नोटरी नियम (संशोधन), 2025 के अनुसार गुजरात में नियुक्त किए जाने वाले नोटरी की अधिकतम संख्या कितनी कर दी गई है?

A) 2,900
B) 4,000
C) 5,000
D) 6,000
E) 7,000

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

• The Department of Legal Affairs notified the Notaries (Amendment) Rules, 2025 through G.S.R. 763(E) published in the Extraordinary Gazette of India, exercising powers under Section 15 of the Notaries Act, 1952.
• विधि कार्य विभाग ने नोटरी नियम (संशोधन), 2025 को भारत के राजपत्र)G.S.R. 763(E)) में अधिसूचित किया, जो नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया।
• The amendment revised the maximum number of Notaries to be appointed by certain State Governments under the Notaries Rules, 1956.
• इस संशोधन के तहत कुछ राज्यों में नियुक्त किए जाने वाले नोटरी की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई है।

Updated limits under Notaries (Amendment) Rules, 2025:

Gujarat**:** 2,900 → 6,000
Tamil Nadu: 2,500 → 3,500
Rajasthan: 2,000 → 3,000
Nagaland**:** 200 → 400

• A Notary is a public official authorized to verify, authenticate, and certify legal documents, witness signatures, and administer oaths.
• नोटरी एक सार्वजनिक अधिकारी होता है जो कानूनी दस्तावेजों को सत्यापित, प्रमाणित और हस्ताक्षरित करने का कार्य करता है तथा शपथ और घोषणाएं दिलाने के लिए अधिकृत होता है।

Ques: According to RBI data, by how much did India's outward remittances for education fall in August 2025 (year-on-year)?
भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, अगस्त 2025 में शिक्षा हेतु विदेश भेजी गई राशि में वर्ष-वर्ष कितनी गिरावट आई-दर?

A) 12%
B) 19%
C) 23.8%
D) 28%
E) 17.7%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• As per RBI's August 2025 data, India's outward remittances for education abroad fell 23.8% year-on-year to $0.32 billion, down from $0.42 billion in August 2024.
• आरबीआई के अगस्त 2025 के आंकड़ों के अनुसार, विदेश में शिक्षा हेतु भेजी गई राशि वर्षवर्ष-दर- 23.8% घटकर $0.32 बिलियन रह गई, जो अगस्त 2024 में $0.42 बिलियन थी।
• This is the lowest monthly figure since August 2017.
• यह अगस्त 2017 के बाद सबसे कम मासिक प्रेषण राशि है।
• Travel-related remittances also declined by 19%, due to tighter immigration and visa norms in countries like the US, UK, and Europe.
• यात्रा संबंधी प्रेषण में भी-19% की गिरावट आई, जो अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप जैसे देशों में कड़े आव्रजन और वीज़ा नियमों के कारण हुई।

Ques: What proposal has the SEBI working group headed by R.S. Gandhi recently made regarding clearing corporations?
हाल ही में R.S. गांधी के नेतृत्व वाले SEBI कार्य समूह ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के संबंध में क्या प्रस्ताव रखा है?

A) Decrease transaction charges / लेनदेन शुल्क घटाना-
B) Merge clearing corporations / क्लियरिंग कॉर्पोरेशन्स का विलय करना
C) Abolish transaction charges / लेनदेन शुल्क समाप्त करना-
D) Keep broker charges higher / ब्रोकर शुल्क बढ़ाना
E) Increase transaction charges / लेनदेन शुल्क बढ़ाना-

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

• A SEBI-constituted working group, headed by Rama Subramaniam (R.S) Gandhi, former Deputy Governor of RBI, has proposed increasing transaction charges for clearing corporations such as NSE Clearing Limited.
• SEBI द्वारा गठित कार्य समूह, जिनका नेतृत्व पूर्व आरबीआई उप-गवर्नर रामा सुब्रमण्यम (R.S) गांधी कर रहे हैं, ने NSE Clearing Limited जैसी क्लियरिंग कॉर्पोरेशनों के लिए लेनदेन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।
• SEBI clarified that broker charges will remain unchanged.
• SEBI ने स्पष्ट किया कि ब्रोकर्स के शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा।
• The move aims to strengthen the financial independence and balance sheets of these clearing corporations.
• इस कदम का उद्देश्य इन क्लियरिंग कॉर्पोरेशनों की वित्तीय स्वतंत्रता और बैलेंस शीट को मजबूत करना है।
• Currently, NSE Clearing receives about 5%–6% of the fees collected by NSE from members, and the revision is expected to raise their share to around 25% or slightly higher.
• वर्तमान में, NSE Clearing को NSE द्वारा सदस्यों से वसूले जाने वाले शुल्क का लगभग 5%–6% मिलता है, और प्रस्तावित संशोधन से यह हिस्सा लगभग 25% या उससे थोड़ा अधिक होने की उम्मीद है।

Ques: What recent change has the Reserve Bank of India (RBI) made regarding the ₹10,000 crore ceiling on bank loans to a single corporate entity?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक) RBI) ने किसी एक कॉर्पोरेट इकाई को दिए जाने वाले 10,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण की सीमा के संबंध में क्या बदलाव किया है?

A) Ceiling reduced to ₹5,000 crore / सीमा 5,000 करोड़ रुपये कर दी गई
B) Ceiling removed entirely / सीमा पूरी तरह हटा दी गई
C) Ceiling increased to ₹15,000 crore / सीमा 15,000 करोड़ रुपये कर दी गई
D) No change to existing ceiling / मौजूदा सीमा में कोई बदलाव नहीं
E) Ceiling replaced by exposure ratio / सीमा को एक्सपोज़र रेशियो से बदल दिया गया

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• The RBI has removed the ₹10,000 crore ceiling on bank loans to a single corporate entity, effective from 1 April 2026, giving banks greater lending flexibility.
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसी एक कॉर्पोरेट इकाई को दिए जाने वाले 10,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण की सीमा हटा दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी, जिससे बैंकों को अधिक ऋण देने की स्वतंत्रता मिलेगी।
• Earlier guidelines (2016) limited concentration risk and encouraged corporates to diversify funding, requiring higher provisions and risk weights if the cap was breached.
• पहले 2016 के दिशानिर्देशों ने सांद्रण जोखिम को सीमित किया और कॉर्पोरेट्स को वित्त पोषण विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित किया, और यदि सीमा पार होती तो अधिक प्रावधान और जोखिम भार लागू करना पड़ता।
• Going forward, the Large Exposures Framework (LEF) will manage concentration risk at the bank level, while systemic risk will be monitored through macroprudential tools.
• अब Large Exposures Framework (LEF) बैंक स्तर पर सांद्रण जोखिम को नियंत्रित करेगा, जबकि प्रणालीगत जोखिम को मैक्रोप्रूडेंशियल टूल्स से मॉनिटर किया जाएगा।
• Under LEF, total exposure to a single borrower cannot exceed 20% of Tier 1 capital, and 25% in case of a corporate group.
• LEF के तहत किसी एक उधारकर्ता के लिए कुल एक्सपोज़र Tier 1 कैपिटल का 20% से

अधिक नहीं हो सकता, और कॉर्पोरेट समूह के लिए यह सीमा 25% है।

Ques: What is the theme of HaRBInger 2025, the innovation challenge organised by RBI?
RBI द्वारा आयोजित HaRBInger 2025 नवाचार चुनौती का विषय क्या है?

A) Digital Payments and Fintech / डिजिटल भुगतान और फिनटेक
B) Secure Banking: Powered by Identity, Integrity and Inclusivity / सुरक्षित बैंकिंगपहचान :, ईमानदारी और समावेशिता द्वारा संचालित
C) Blockchain and Cryptocurrency / ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी
D) Financial Literacy for All / सभी के लिए वित्तीय साक्षरता
E) AI in Banking / बैंकिंग में एआई

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• HaRBInger 2025 – Innovation for Transformation is the 4th edition organised by the Reserve Bank of India.
• HaRBInger 2025 – इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित चौथा संस्करण है।
• The theme of this edition is Secure Banking: Powered by Identity, Integrity and Inclusivity.
• इस संस्करण का विषय है सुरक्षित बैंकिंगपहचान :, ईमानदारी और समावेशिता द्वारा संचालित।
• The event is conducted by the Reserve Bank Innovation Hub (RBIH) and focuses on problem statements like Tokenised KYC, Offline CBDC (e₹), and Enhancing trust.
• इस कार्यक्रम का संचालन रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब)RBIH) करता है और यह Tokenised KYC, Offline CBDC (e₹), और भरोसे को बढ़ाने जैसी समस्याओं पर केंद्रित है।

Prize of HaRBInger 2025:

- Winner across each problem statement : ₹40 lakh
- Runner-up across each problem statement : ₹20 lakh

- Special prize to the best ‘all woman team’ (a team comprising of only woman members’), across all the three problem statements : ₹20 lakh
- Stipend for each team shortlisted for solution development phase (for meeting the cost of development of prototype) : ₹5 lakh

---

Ques: What was the average daily transaction value of UPI in October 2025 according to NPCI data?
NPCI के अनुसार अक्टूबर 2025 में UPI का औसत दैनिक लेनदेन मूल्य कितना था?

A) ₹75,000 crore
B) ₹84,000 crore
C) ₹94,000 crore
D) ₹1 lakh crore
E) ₹64,000 crore

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• According to NPCI, UPI recorded an average daily transaction value of ₹94,000 crore in October 2025, a 13% rise over September.
• NPCI के अनुसार, अक्टूबर 2025 में UPI ने औसत दैनिक लेनदेन मूल्य ₹94,000 करोड़ दर्ज किया, जो सितंबर की तुलना में 13% अधिक है।
• UPI also hit a record 740 million transactions in a single day during Diwali, highlighting India’s growing digital payment adoption.
• दीवाली के दिन UPI ने एक ही दिन में रिकॉर्ड 740 मिलियन लेनदेन दर्ज किए, जो भारत में डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है।
• Experts expect total monthly UPI transactions to cross ₹28 lakh crore, marking an all-time high.
• विशेषज्ञों का अनुमान है कि कुल मासिक UPI लेनदेन मूल्य ₹28 लाख करोड़ को पार कर सकता है, जो अब तक का सबसे उच्च स्तर होगा।

Ques: Which bank has signed an MoU with DPIIT to provide enhanced support for startups in India?

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन DPIIT ने भारत में स्टार्टअप्स को बेहतर समर्थन देने के लिए किस बैंक के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं?

A) HDFC Bank / HDFC बैंक
B) ICICI Bank / ICICI बैंक
C) Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक
D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
E) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), under the Ministry of Commerce and Industry, signed an MoU with Kotak Mahindra Bank Ltd. to enhance financial and non-financial support for startups across India.
• केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन DPIIT ने भारत में स्टार्टअप्स को वित्तीय और गैर-वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
• Under this MoU, Kotak Mahindra Bank will offer zero-balance current accounts, working capital and term loans, API-based banking platforms, digital payment solutions, and specialized startup cards to DPIIT-recognised startups.
• इस MoU के तहत कोटक महिंद्रा बैंक DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को शून्य-शेष चालू खाते, वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन, API आधारित बैंकिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल भुगतान समाधान और विशेष स्टार्टअप कार्ड प्रदान करेगा।
• The bank will also facilitate access to mentorship, investment advisory, incubation support, and networking platforms, aiding startups from ideation to scaling their business.
• बैंक स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, निवेश सलाह, इनक्यूबेशन समर्थन और नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म तक पहुंच भी प्रदान करेगा, जिससे वे विचार से अपने व्यवसाय को बढ़ाने तक प्रगति कर सकेंगे।

Ques: Which bank received the titles of 'World's Best Consumer Bank 2025' and 'Best Bank in India 2025'?
किस बैंक को 'विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025' और 'भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025' का खिताब मिला?

A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
C) Axis Bank / एक्सिस बैंक
D) State Bank of India (SBI) / भारतीय स्टेट बैंक)SBI)
E) Bank of Baroda / बैंक ऑफ़ बड़ौदा

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

• State Bank of India (SBI) received two prestigious awards from Global Finance, New York during the World Bank/IMF Annual Meetings 2025.
• भारतीय स्टेट बैंक)SBI) को ग्लोबल फाइनेंस, न्यूयॉर्क से विश्व बैंकआईएमएफ वार्षिक / बैठक2025 के दौरान दो प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले।
• SBI won the titles of 'World's Best Consumer Bank 2025' and 'Best Bank in India 2025', recognizing its strong performance and customer-focused digital initiatives.
• एसबीआई को 'विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025' और 'भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025' का खिताब मिला, जो इसके मजबूत प्रदर्शन और ग्राहकेंद्रित डिजिटल पहलों को दर्शाता - है।

Ques: What is the total value of Phase-I of the Amaravati Capital City Development Project in Andhra Pradesh?
आंध्र प्रदेश में अमरावती राजधानी शहर विकास परियोजना के फेज-I का कुल मूल्य क्या है?

A) ₹10,000 crore
B) ₹12,500 crore
C) ₹15,000 crore
D) ₹16,500 crore
E) ₹18,000 crore

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• Phase-I of the Amaravati Capital City Development Project in Andhra Pradesh has a total project value of ₹15,000 crore.
• आंध्र प्रदेश में अमरावती राजधानी शहर विकास परियोजना का फेज-I का कुल मूल्य ₹15,000 करोड़ है।
• The implementing agency for the project is the Andhra Pradesh Capital Region Development Authority (APCRDA).
• इस परियोजना को लागू करने वाली एजेंसी आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी)APCRDA) है।
• Funding for Phase-I comes from the Government of India (₹1,400 crore), the World Bank (IBRD, USD 800 million), and the Asian Development Bank (ADB, USD 800 million).
• फेज-I के लिए वित्तपोषण भारत सरकार)₹1,400 करोड़(, वर्ल्ड बैंक)IBRD, USD 800 मिलियन) ट बैंकऔर एशियन डेवलपमें (ADB, USD 800 मिलियनसे प्राप्त होता है। (
• The first tranche from the World Bank, USD 207 million (≈ ₹1,800 crore), was released in March 2025, with the next contribution of USD 200 million expected by December 2025.
• वर्ल्ड बैंक की पहली किश्त USD 207 मिलियन)≈ ₹1,800 करोड़ मार्च (2025 में जारी की गई थी, और अगली योगदान राशि USD 200 मिलियन दिसंबर 2025 तक अपेक्षित है।
• In total, the World Bank and ADB together are contributing USD 1,600 million (≈ ₹13,600 crore) for Phase-I.
• कुल मिलाकर, वर्ल्ड बैंक और ADB फेज-I के लिए मिलकर USD 1,600 मिलियन)≈ ₹13,600 करोड़का योगदान दे रहे हैं। (

Ques: Which new feature has the Reserve Bank of India (RBI) launched to enable digital rupee payments without Internet or telecom connectivity?
भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने बिना इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी के डिजिटल रुपये से भुगतान करने के लिए कौनसी नई सुविधा शुरू की है-?

(a) e₹ Connect
(b) e₹ Smart Pay
(c) Offline Digital Rupee
(d) UPI Lite+

(e) BharatPay e₹

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has introduced an offline digital rupee feature allowing users to make payments even without Internet or telecom connectivity.
• भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने ऑफ़लाइन डिजिटल रुपया सुविधा शुरू की है, जिससे उपयोगकर्ता बिना इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी के भी भुगतान कर सकते हैं।
• The feature was announced at the Global Fintech Fest 2025 held in Mumbai in October 2025.
• यह सुविधा अक्टूबर 2025 में मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में घोषित की गई थी।
• The offline e₹ works on two technologies — Near Field Communication (NFC) for tap-based transfers and telecom-assisted payments for low-signal areas.
• ऑफ़लाइन e₹ दो तकनीकों पर कार्य करता है — निकट क्षेत्र संचार)NFC) और टेलीकॉम-सहायता प्राप्त भुगतान, जो कम नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी काम करता है।
• Unlike UPI, which needs an online connection, the Digital Rupee allows direct wallet-to-wallet transfers without requiring a bank account.
• UPI के विपरीत, डिजिटल रुपया वॉलेटवॉलेट सीधे हस्तांतरण की सुविधा देता है-टू-, जिसमें बैंक खाते की आवश्यकता नहीं होती।
• The digital wallet can be downloaded via official apps from 15 participating banks, including SBI, HDFC Bank, and ICICI Bank.
• डिजिटल वॉलेट को 15 भागीदार बैंकों जैसे)SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंकके (
किया जा सकता है। आधिकारिक ऐप्स से डाउनलोड
• Wallets have no minimum balance requirement, with a daily cap of ₹50,000 or 20 transactions, and a maximum wallet balance of ₹1 lakh.
• वॉलेट में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है, जबकि दैनिक सीमा ₹50,000 या 20 लेनदेन की है और अधिकतम शेष ₹1 लाख से अधिक नहीं हो सकता।

Ques: As of September 2025, what was the total value of RBI's gold reserves?
सितंबर 2025 तक RBI के स्वर्ण भंडार का कुल मूल्य कितना था?

A) $85 billion
B) $90 billion
C) $95 billion
D) $100 billion
E) $105 billion

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• As per the latest data, the Reserve Bank of India (RBI)'s gold reserves crossed 880 metric tonnes in the first half of FY 2025-26.
• नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) के स्वर्ण भंडार 880 मीट्रिक टन पार कर गए।
• The central bank added 0.2 metric tonnes of gold in the last week of September 2025.
• केंद्रीय बैंक ने सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में 0.2 मीट्रिक टन सोना जोड़ा।
• The total value of RBI's gold holdings stood at $95 billion as of September 26, 2025, reflecting continued growth and diversification of foreign exchange assets.
• 26 सितंबर 2025 तक RBI के स्वर्ण भंडार का कुल मूल्य $95 बिलियन था, जो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के विविधीकरण और निरंतर वृद्धि को दर्शाता है।

Ques: According to the Reserve Bank of India (RBI), what percentage of total payment transaction volume in India was conducted through digital modes in the first half of 2025?
भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) के अनुसार, 2025 की पहली छमाही में भारत में कुल भुगतान लेनदेन की मात्रा का कितना प्रतिशत डिजिटल माध्यमों से किया गया-?

A) 96.7%
B) 97.7%
C) 99.8%
D) 95.5%

E) 98.6%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• The payments ecosystem in India has seen remarkable growth, with digital payments accounting for 99.8% of total payment transaction volume in the first half of 2025.
• भारत में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र ने उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जहाँ डिजिटल भुगतान 2025 की पहली छमाही में कुल लेन देन की मात्रा का-99.8% हिस्सा रहे।
• In terms of value, digital payments contributed *97.7%* of total payment transactions during this period, as per data released by the *Reserve Bank of India (RBI).*
• मूल्य के दृष्टिकोण से, *भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI)* के अनुसार, इस अवधि में डिजिटल भुगतानों का योगदान कुल लेनदेन का- 97.7% रहा।
• Total payment transactions stood at ₹1,572 lakh crore, out of which ₹1,536 lakh crore were made digitally.
• कुल भुगतान लेन देन-₹1,572 लाख करोड़ रहे, जिनमें से ₹1,536 लाख करोड़ डिजिटल माध्यमों से किए गए।
• UPI accounted for *85% of total transactions by volume* and *9% by value*, while RTGS had the *highest value share (69%)* despite contributing just *0.1%* of the total volume.
• यूपीआई ने *कुल लेन में देन की मात्रा-85%* और *मूल्य में 9%* हिस्सेदारी रखी, जबकि *आरटीजीएस* ने *मूल्य के आधार पर 69%* की सर्वाधिक हिस्सेदारी दर्ज की, भले ही उसका वॉल्यूम हिस्सा केवल *0.1%* रहा।
• In the first half of 2025, *UPI* processed *10,637 crore transactions* worth ₹143.3 lakh crore, whereas *RTGS* handled *16.1 crore transactions* valued at ₹1,079.2 lakh crore.
• 2025 की पहली छमाही में *यूपीआई* ने *10,637 करोड़ लेनदेन-* ₹143.3 लाख करोड़ के मूल्य के साथ किए, जबकि *आरटीजीएस* ने *16.1 करोड़ लेनदेन-* ₹1,079.2 लाख करोड़ के मूल्य के साथ किए।
• Over the last five years, India's digital payments have increased *6.6 times in volume* and *1.6 times in value*.
• पिछले पाँच वर्षों में, भारत में डिजिटल भुगतानों में *मात्रा के आधार पर 6.6 गुना* और *मूल्य के आधार पर 1.6 गुना* वृद्धि हुई है।

Ques: Which investment options have been extended to Central Government employees under NPS and UPS?
केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए NPS और UPS के तहत कौनकौन से निवेश विकल्प - बढ़ाए गए हैं?

A) LC25, LC50, LC75 / LC25, LC50, LC75
B) Default option, Scheme G / डिफ़ॉल्ट विकल्प, योजना G
C) BLC (Balanced Life Cycle) / BLC (संतुलित जीवन चक्र(
D) All of the above / उपरोक्त सभी
E) None of the above / इनमें से कोई नहीं

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

• The Government of India has approved the extension of LC75 and BLC investment options to Central Government employees under both the National Pension System (NPS) and the Unified Pension Scheme (UPS).
• भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली)NPS) और यूनिफाइड पेंशन योजना)UPS) के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए LC75 और BLC निवेश विकल्प बढ़ाने को मंजूरी दी है।
• Under NPS and UPS, employees can choose from a range of options: Default option (as defined by PFRDA), Scheme G (100% in government securities), LC25, LC50, LC75, and BLC.
• NPS और UPS के तहत कर्मचारियों के पास विभिन्न विकल्प चुनने की सुविधा हैडिफ़ॉल्ट :) विकल्पPFRDA द्वारा परिभाषित(, योजना G (100% सरकारी प्रतिभूतियों में(, LC25, LC50, LC75 और BLC।
• LC75 allows maximum 75% equity allocation tapering gradually from age 35 to 55, LC50 allows 50%, LC25 allows 25%, while BLC is a modified LC50 tapering from age 45 for equity.
• LC75 अधिकतम 75% इक्विटी आवंटन की अनुमति देता है, जो 35 से 55 वर्ष की आयु तक धीरेधीरे घटती है-; LC50 में 50%, LC25 में 25% की अनुमति है, जबकि BLC एक संशोधित LC50 है जिसमें 45 वर्ष की आयु से इक्विटी घटती है।
• These options give employees flexibility to choose risk-return profiles suited to their investment goals and retirement planning.
• ये विकल्प कर्मचारियों को उनके निवेश लक्ष्यों और सेवानिवृत्ति योजना के अनुसार जोखिमइल चुनने में लचीलापन प्रदान करते हैं।रिटर्न प्रोफ़ा-

Ques: According to the RBI's Payment Systems Report, how did credit and debit card transactions in India change between 2019 and 2024?
RBI के पेमेंट सिस्टम्स रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2024 के बीच भारत में क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेनदेन में क्या बदलाव हुआ?

A) Both credit and debit card transactions increased / क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेनदेन दोनों बढ़े
B) Credit card transactions increased, debit card transactions decreased / क्रेडिट कार्ड लेनदेन बढ़े, डेबिट कार्ड लेनदेन घटे
C) Credit card transactions decreased, debit card transactions increased / क्रेडिट कार्ड लेनदेन घटे, डेबिट कार्ड लेनदेन बढ़े
D) Both credit and debit card transactions decreased / क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेनदेन दोनों घटे
E) No significant change in either / दोनों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• The RBI's Payment Systems Report highlighted that between 2019 and 2024, credit card transactions in India doubled in volume (from 2,087 million to 4,472 million) and nearly tripled in value (from Rs 7.1 trillion to Rs 20.4 trillion).
• RBI की पेमेंट सिस्टम्स रिपोर्ट में बताया गया कि 2019 से 2024 के बीच भारत में क्रेडिट कार्ड लेनदेन मात्रा में दोगुना)2,087 मिलियन से 4,472 मिलियनऔर मूल्य में लगभग ( ) तीन गुना₹7.1 ट्रिलियन से ₹20.4 ट्रिलियनबढ़ा। (
• In contrast, debit card transactions declined in both volume (4,953 million to 1,738 million) and value (Rs 6.83 trillion to Rs 5.15 trillion) during the same period.
• इसके विपरीत, डेबिट कार्ड लेनदेन मात्रा में)4,953 मिलियन से 1,738 मिलियनऔर ( ) मूल्य में₹6.83 ट्रिलियन से ₹5.15 ट्रिलियनघटा। (
• Private sector banks dominate the credit card segment, with their market share rising from 65.8% in June 2020 to 70.8% in June 2025. Public sector banks' share also increased slightly from 22.5% to 24.1% during the same period.
• निजी क्षेत्र के बैंक क्रेडिट कार्ड खंड में प्रमुख हैं, जिनकी बाजार हिस्सेदारी जून 2020 में 65.8% से बढ़कर जून 2025 में 70.8% हो गई। इसी अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शेयर भी 22.5% से 24.1% तक बढ़ा।

Ques: As per the Union Ministry of Cooperation, which cooperative societies will now serve as Bank Mitras of District Central and State Cooperative Banks?

सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, अब कौनसी सहकारी समितियाँ जिला केंद्रीय और राज्य - बैंक मित्र के रूप में कार्य करेंगी सहकारी बैंकों की?

(a) Agricultural and Credit Cooperative Societies / कृषि और ऋण सहकारी समितियाँ
(b) Dairy and Fisheries Cooperative Societies / डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियाँ
(c) Women Self-Help Groups / महिला स्वसहायता समूह-
(d) Rural Development Cooperatives / ग्रामीण विकास सहकारी समितियाँ
(e) Housing Cooperative Societies / आवास सहकारी समितियाँ

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• The Union Ministry of Cooperation announced that, under the vision of "Sahkar Se Samriddhi," dairy and fisheries cooperative societies will act as Bank Mitras of District Central Cooperative Banks (DCCBs) and State Cooperative Banks (STCBs).
• सहकारिता मंत्रालय ने "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण के तहत घोषणा की कि डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियाँ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक)DCCB) और राज्य सहकारी बैंक)STCB) की बैंक मित्र के रूप में कार्य करेंगी।
• With the support of NABARD, the Ministry has initiated efforts to connect cooperative societies with cooperative banks.
• NABARD के सहयोग से मंत्रालय ने सहकारी समितियों को सहकारी बैंकों से जोड़ने की पहल शुरू की है।
• A pilot programme in Gujarat (Banaskantha & Panchmahal) enabled cooperatives to open deposit accounts and issue RuPay Kisan Credit Cards (KCCs).
• गुजरात में एक पायलट कार्यक्रम के तहत सहकारी समितियों (बनासकांठा और पंचमहाल)) ने जमा खाते खोले और रूपे किसान क्रेडिट कार्डKCC) जारी किए।
• So far, 12,580 Micro-ATMs have been distributed to Bank Mitra Cooperative Societies in Gujarat.
• अब तक गुजरात में बैंक मित्र सहकारी समितियों को 12,580 माइक्रोएटीएम वितरित - किए जा चुके हैं।

Ques: From which date will the key provisions relating to nomination under the Banking Laws (Amendment) Act, 2025 come into effect?
2025 के बैंकिंग कानून किस अधिनियम में नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान (संशोधन) तिथि से लागू होंगे?

A) 15th April 2025
B) 1st October 2025
C) 1st November 2025
D) 1st December 2025
E) 15th November 2025

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• The Banking Laws (Amendment) Act, 2025 was notified on 15th April 2025, containing 19 amendments across five legislations including RBI Act, Banking Regulation Act, SBI Act, and Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts of 1970 & 1980.
• बैंकिंग कानून अधिनियम (संशोधन), 2025 को 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें आरबीआई अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम, एसबीआई अधिनियम और 1970 एवं 1980 के बैंकिंग कंपनियों अधि (अधिग्रहण और हस्तांतरण)नियम सहित पांच कानूनों में कुल 19 संशोधन शामिल हैं।
• The Central Government has notified that Sections 10, 11, 12, and 13, related to nomination facilities for deposit accounts, safe custody articles, and locker contents, will come into force from 1st November 2025.
• केंद्रीय सरकार ने अधिसूचित किया है कि धारा 10, 11, 12 और 13, जो जमा खातों, सुरक्षित भंडारण की वस्तुओं और लॉकर सामग्री के लिए नामांकन सुविधाओं से संबंधित हैं, 1 नवंबर 2025 से लागू होंगी।
• Key features include multiple nominations (up to four persons simultaneously or successively), specifying shares for simultaneous nominations, and ensuring successive nominees become operative only upon the death of the prior nominee.
• मुख्य विशेषताओं में एक से अधिक नामांकनों की अनुमति एक साथ या क्रमिक र)ूप से अधिकतम चार व्यक्ति(, एक साथ नामांकनों के लिए शेयर निर्दिष्ट करना और क्रमिक नामांकनों में अगले नामांकित केवल पूर्व नामांकित की मृत्यु पर सक्रिय होना शामिल है।
• These provisions aim to simplify claim settlement and ensure clarity and continuity in succession for deposits and bank locker contents.

• ये प्रावधान दावों के निपटान को सरल बनाने और जमा और बैंक लॉकर सामग्री के उत्तराधिकार में स्पष्टता और निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं।

Ques: Which new entity is being established to strengthen real-time fraud detection and risk management in India's banking system?
भारत में बैंकिंग प्रणाली में वास्तविक समय धोखाधड़ी पहचान और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कौन सी नई संस्था स्थापित की जा रही है?

A) Indian Banking Fraud Authority / भारतीय बैंकिंग फ्रॉड अथॉरिटी
B) Indian Digital Payment Intelligence Corporation / भारतीय डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन
C) National Financial Risk Bureau / राष्ट्रीय वित्तीय जोखिम ब्यूरो
D) Fraud Monitoring & Analytics Centre / फ्रॉड मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स सेंटर
E) Digital Banking Security Agency / डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा एजेंसी

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• The Indian Digital Payment Intelligence Corporation (IDPIC) is being established to enhance real-time fraud detection and strengthen risk management across India's financial system.
• भारतीय डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन)IDPIC) को भारत की वित्तीय प्रणाली में वास्तविक समय धोखाधड़ी पहचान और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए स्थापित किया जा रहा है।
• The initiative is led by the State Bank of India (SBI) and Bank of Baroda (BoB), with support from other public sector banks.
• यह पहल भारतीय स्टेट बैंक)SBI) और बैंक ऑफ़ बड़ौदा)BoB) द्वारा नेतृत्व की जा रही है, जिसमें अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समर्थन भी शामिल है।
• IDPIC has been approved by the RBI as a Section 8 not-for-profit company, with an authorized capital of ₹500 crore and paid-up capital of ₹200 crore. SBI has committed ₹10 crore as initial funding, which Bank of Baroda is expected to match.
• RBI ने IDPIC को सेक्शन 8 कंपनी के रूप में अनुमोदित किया है, जिसका अधिकृत पूंजी ₹500 करोड़ और भरी हुई पूंजी ₹200 करोड़ है। संचालन शुरू करने के लिए SBI ने ₹10

करोड़ का प्रारंभिक योगदान दिया है, जिसे बैंक ऑफ़ बड़ौदा से मिलान करने की उम्मीद है।
• Bank frauds have nearly tripled in FY25, with the total amount rising from ₹12,230 crore in the previous year to ₹36,014 crore.
• FY25 में बैंक धोखाधड़ी लगभग तीन गुना बढ़ गई, कुल राशि पिछले वर्ष ₹12,230 करोड़ से बढ़कर ₹36,014 करोड़ हो गई।

Ques: Which organization launched the AI-powered digital assistant 'UPI Help' to simplify grievance redressal and transaction tracking?
किस संगठन ने शिकायत निवारण और लेनदेन ट्रैकिंग को स-रल बनाने के लिए AI-पावर्ड डिजिटल असिस्टेंट 'UPI Help' लॉन्च किया?

A) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक
B) Paytm / पेटीएम
C) State Bank of India (SBI) / भारतीय स्टेट बैंक
D) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
E) National Payments Corporation of India (NPCI) / राष्ट्रीय भुगतान निगम

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

• The National Payments Corporation of India (NPCI) launched 'UPI Help', an AI-powered digital assistant designed to simplify grievance redressal and transaction tracking on the Unified Payments Interface (UPI).
• राष्ट्रीय भुगतान निगम)NPCI) ने 'UPI Help' लॉन्च किया, जो AI-पावर्ड डिजिटल असिस्टेंट है और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस)UPI) पर शिकायत निवारण और लेनदेन - ए डिज़ाइन किया गया है।ट्रैकिंग को सरल बनाने के लि
• The assistant is integrated with the UPI Dispute Resolution (UDIR) system, standardizing complaint handling across banks and payment service providers.
• यह असिस्टेंट UPI डिस्प्यूट रेज़ॉल्यूशन)UDIR) सिस्टम के साथ एकीकृत है, जो बैंकों और पेमेंट सेवा प्रदाताओं के बीच शिकायत निवारण को मानकीकृत करता है।
• Initially launched as a pilot, 'UPI Help' will be available via member banks' portals, DigiSaathi chatbot, and websites for select users.
• शुरू में पायलट के रूप में लॉन्च किए गए 'UPI Help' को चुनिंदा उपयोगकर्ताओं के लिए सदस्य बैंकों के पोर्टल, DigiSaathi चैटबोट और वेबसाइट्स के माध्यम से उपलब्ध कराया

जाएगा।

Ques: Which global investment firm announced plans to acquire a 9.99% stake in Federal Bank Limited?
कौन सी वैश्विक निवेश फर्म ने Federal Bank Limited में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की योजना की घोषणा की?

A) KKR / केकेआर
B) TPG Capital / टीपीजी कैपिटल
C) Carlyle Group / कार्लाइल ग्रुप
D) Bain Capital / बैन कैपिटल
E) Blackstone Inc. / ब्लैकस्टोन इंक.

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

• Blackstone Inc. announced plans to acquire a minority stake of 9.99% in Federal Bank Limited for Rs 6,196.51 crore.
• ब्लैकस्टोन इंक ने .Federal Bank Limited में 9.99% अल्पसंख्यक हिस्सेदारी खरीदने की योजना की घोषणा की, जिसकी कीमत ₹6,196.51 करोड़ है।
• As part of the deal, Federal Bank will issue 27.29 crore warrants to Blackstone's affiliate, Asia II Topco XIII Private Limited, at Rs 227 per warrant.
• इस सौदे के तहत, Federal Bank 27.29 करोड़ वॉरंट्स ब्लैकस्टोन की सहायक कंपनी Asia II Topco XIII Private Limited को ₹227 प्रति वॉरंट के हिसाब से जारी करेगा।
• These warrants give Blackstone the right to buy shares at a fixed price within 18 months; if not converted, the initial payment is forfeited.
• ये वॉरंट्स ब्लैकस्टोन को 18 महीनों के भीतर निश्चित मूल्य पर शेयर खरीदने का अधिकार देते हैं; यदि उन्हें रूपांतरित नहीं किया गया, तो प्रारंभिक भुगतान जब्त हो जाएगा।

Ques: As per SEBI's new proposal, after how many years from maturity will unclaimed amounts from non-convertible securities be transferred to the IEPF?

SEBI के नए प्रस्ताव के अनुसार, नॉनकन्वर्टिबल सिक्योरिटीज से अनक्लेम्ड राशि को - परिपक्वता के कितने वर्षों बादIEPF में ट्रांसफर किया जाएगा?

A) 3 years
B) 5 years
C) 7 years
D) 10 years
E) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• SEBI has proposed amendments to standardize the treatment of unclaimed amounts from non-convertible securities, aligning them with the Companies Act, 2013 and IEPF Rules.
• SEBI ने नॉनकन्वर्टिबल सिक्योरिटीज से अनक्लेम्ड राशि के प्रावधानों को कंपनी - अधिनियम, 2013 और IEPF नियमों के अनुरूप मानकीकृत करने का प्रस्ताव दिया है।
• Under the new guidelines, unclaimed amounts related to matured debentures, including accrued interest, will be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) only after seven years from the date of maturity.
• नए दिशानिर्देशों के तहत म्याच्योर डिबेंचर और ब्याज सहित अनक्लेम्ड राशि को - परिपक्वता की तारीख से सात वर्ष बाद हीIEPF में ट्रांसफर किया जाएगा।
• This replaces the existing inconsistency in LODR Regulation 61A(3), which required transfer of unclaimed interest even before debenture maturity.
• यह LODR रेगुलेशन 61A(3) में मौजूद असंगति को दूर करता है, जिसमें डिबेंचर के परिपक्व होने से पहले भी अनक्लेम्ड ब्याज को ट्रांसफर करने का प्रावधान था।

Ques: The Reserve Bank of India (RBI) has released a draft circular proposing limits on banks' exposure to which sectors?
भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने बैंकों के किस क्षेत्र में निवेश पर सीमा निर्धारित करने का मसौदा परिपत्र जारी किया है?

A) Infrastructure and Real Estate / अवसंरचना और रियल एस्टेट
B) Renewable Energy Projects / नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ
C) MSMEs and Startups / सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं स्टार्टअप
D) Agriculture and Rural Credit / कृषि और ग्रामीण ऋण
E) Capital Markets and Acquisition Finance / पूंजी बाजार और अधिग्रहण वित्त

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) released a draft circular proposing limits on banks' exposure to capital markets and acquisition finance.
• भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने बैंकों के पूंजी बाजार और अधिग्रहण वित्त में निवेश पर सीमा निर्धारित करने के लिए मसौदा परिपत्र जारी किया है।
• The proposed rationalised norms are expected to be implemented from April 1, 2026.
• प्रस्तावित तर्कसंगत मानदंड 1 अप्रैल 2026 से लागू किए जाएंगे।
• Under the draft guidelines, a bank's total exposure towards acquisition finance must not exceed 10% of its Tier 1 capital.
• मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार-, बैंक का अधिग्रहण वित्त के प्रति कुल जोखिम उसकी टियर-1 पूंजी का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
• Banks' total direct investments in capital markets and acquisition finance must not exceed 20% of their Tier 1 capital.
• बैंकों का पूंजी बाजार और अधिग्रहण वित्त में कुल प्रत्यक्ष निवेश उनकी टियर-1 पूंजी का 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।
• Additionally, the aggregate capital market exposure of banks should not exceed 40% of their Tier 1 capital.
• इसके अतिरिक्त, बैंकों का कुल पूंजी बाजार जोखिम उनकी टियर-1 पूंजी का 40% से अधिक नहीं होना चाहिए।
• Banks may finance up to 70% of the deal value, while the acquiring company must fund at least 30%.
• बैंक सौदे के मूल्य का 70% तक वित्तपोषण कर सकते हैं, जबकि अधिग्रहण करने वाली

कंपनी को कम से कम 30% स्वयं वहन करना होगा।
• Acquisition finance can be offered only to listed companies with satisfactory net worth and profitability for the last three years.
• अधिग्रहण वित्त केवल सूचीबद्ध कंपनियों को ही प्रदान किया जा सकेगा, जिनकी नेट वर्थ संतोषजनक हो और जो पिछले तीन वर्षों से लाभ में रही हों।

Ques: As per RBI's draft guidelines, what is the maximum percentage of acquisition value that banks can finance?
RBI के ड्राफ्ट दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक अधिग्रहण मूल्य का अधिकतम कितना प्रतिशत वित्तपोषण कर सकते हैं?

A) 50%
B) 60%
C) 70%
D) 80%
E) 100%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has proposed allowing banks to finance up to 70% of the acquisition value for corporate takeovers.
• भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने प्रस्ताव दिया है कि बैंक कॉरपोरेट अधिग्रहणों के लिए अधिग्रहण मूल्य का 70% तक वित्तपोषण कर सकेंगे।
• The remaining 30% must be funded by the acquiring company through its own equity or internal resources.
• शेष 30% अधिग्रहणकर्ता कंपनी को अपनी स्वयं की पूंजी या आंतरिक संसाधनों से जुटाने होंगे।
• This marks a major policy shift, as earlier Indian banks were not allowed to fund corporate acquisitions directly.
• यह एक बड़ा नीतिगत परिवर्तन है, क्योंकि पहले भारतीय बैंकों को सीधे कॉरपोरेट अधिग्रहणों के लिए फंडिंग की अनुमति नहीं थी।
• Only listed companies with a profit record of at least three years will be eligible for such financing.
• केवल वे सूचीबद्ध कंपनियां जिनका कम से कम तीन वर्षों का लाभ रिकॉर्ड है, इस प्रकार

के वित्तपोषण के लिए पात्र होंगी।

Ques: Which bank recently joined other lenders in labeling Reliance Communications' ₹488 crore loan as fraudulent?
हाल ही में किस बैंक ने अन्य ऋणदाताओं के साथ रिलायंस कम्युनिकेशंस के ₹488 करोड़ के ऋण को धोखाधड़ी वाला)fraudulent) करार दिया?

A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
B) Bank of Baroda / बैंक ऑफ़ बड़ौदा
C) Bank of Maharashtra / महाराष्ट्र बैंक
D) Bank of India / बैंक ऑफ़ इंडिया
E) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• The Bank of Maharashtra has joined three other lenders—State Bank of India, Bank of Baroda, and Bank of India—in labeling Reliance Communications' ₹488 crore loan as fraudulent, adding to the telecom company's financial troubles.
• महाराष्ट्र बैंक ने अन्य तीन ऋणदाताओं—भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा और बैंक ऑफ़ इंडिया—के साथ मिलकर रिलायंस कम्युनिकेशंस के ₹488 करोड़ के ऋण को धोखाधड़ी वाला)fraudulent) घोषित किया है, जिससे टेलीकॉम कंपनी की वित्तीय परेशानियाँ बढ़ गई हैं।
• Reliance Communications is already undergoing a Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016.
• रिलायंस कम्युनिकेशंस पहले ही 2016 के दिवालियापन और दिवालियापन संहिता)IBC) के तहत कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया)CIRP) से गुजर रहा है।

About Bank Of Maharashtra :

- Established : 1935
- HQ : Pune, Maharashtra

- MD & CEO : Nidhu Saxena
- Tagline : One Family One Bank

Ques: When was the SWAMIH Fund announced by the Government of India?
भारत सरकार द्वारा SWAMIH फंड की घोषणा कब की गई थी?

A) 6 November 2019
B) 10 March 2020
C) 1 January 2021
D) 5 May 2018
E) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

• The SWAMIH (Special Window for Affordable and Mid-Income Housing) Fund was announced on 6 November 2019 as a 'Special Window' to support completion of stalled housing projects.
• SWAMIH (सस्ती और मध्यम फंड की घोषणा (आय आवास के लिए विशेष विंडो-6 नवंबर 2019 को एक 'विशेष विंडो' के रूप में की गई थी ताकि अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने में सहायता की जा सके।
• It operates as an Alternative Investment Fund (AIF) aimed at providing priority debt financing for such projects.
• यह एक वैकल्पिक निवेश फंड)AIF) के रूप में कार्य करता है, जो ऐसी परियोजनाओं के लिए प्राथमिक ऋण वित्तपोषण प्रदान करता है।
• SBI Ventures acts as the investment manager of the SWAMIH Fund under RBI supervision.
• RBI के पर्यवेक्षण में SBI वेंचर्स SWAMIH फंड के निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करता है।